राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहीदी मानगढ़ धाम पर आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानगढ़ विकास के लिये पांच करोड़ रुपये एवं पुलिस चौकी स्थापित करने की घोषणा की। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा अगर कोई जल-जंगल -जमीन बचा रहा है तो वह आदिवासी है और आदिवासी ही प्रकृति का संरक्षण करते हैं।

जनजातीय गौरव से देश में नई चेतना का संचार हुआ है- राष्ट्रपति

भानगढ़ धाम में मुख्यमंत्री ने सीतामाता, त्रिपुर सुंदरी, मानगढ़-बेणेश्वर पर्यटन सर्किट बनाने का निर्णय की घोषणा की

- **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के आदिवासी खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की।**
- **राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि जल-जंगल-जमीन को केवल आदिवासी ही बचा रहा हैं। आदिवासी ही प्रकृति का संरक्षण करता है।**

बांसवाड़ा, 4 अक्टूबर (निसं)। हल्दी घाटी से लेकर शहीदी मानगढ़ धाम की रज पर आदिवासियों के त्याग, समर्पण और राष्ट्र प्रेम की गाथा की महक महसूस की जा सकती है। आदिवासी वीरों के बलिदान की साक्षी रही ये भूमि हमारा जज़्बा जागृत करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदी मानगढ़ धाम पर आयोजित ''आदि गौरव सम्मान'' समारोह के दौरान उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर ''धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान'' का शुभारंभ किया है। इस अभियान से पांच करोड़ से अधिक जनजाति समाज के लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें पवित्र मानगढ़ धाम पर गोविन्द गिरि की अलौकिक ज्योति की प्रतीक, धूणी के दर्शन का अवसर मिला और शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। उन्होंने बताया कि आने वाले 30 अक्टूबर को हम गोविन्द गुरु की पुण्यतिथि मनायेंगे। इसके बाद 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सभी देशवासी जनजातीय गौरव दिवस के रुप में मनायेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय गौरव के बारे में देश में एक नई चेतना का संचार हुआ है।

राष्ट्रपति ने जनजाति बहुल ग्रामों में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा और पोषण प्रदान करने के लिये स्थापित मां-बाड़ी समूहों की माताओं और बच्चों से मिलकर अपनी अनुभूतियों को भी बयान किया, वहीं तीरंदाजी और लैक्रोस के बारे में मिली उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की आदिवासी बेटी सुनीता मीना देश की लैक्रोस टीम की कप्तान चुनी गयी है। राजस्थान के जनजातीय समाज के बेटे और बेटियां खेलकूद की राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आदिवासी समाज, राज्य और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 17 नवंबर 1913 हमारे स्वाधीनता संग्राम तथा जनजातीय आंदोलनों की दुखद् तारीख है। इसी दिन मानगढ़ धाम में अंग्रेजों ने भील समुदाय के1500 से अधिक बहादुरों की निर्मम हत्या की थी। उन्होंने कहा कि इस गौरवशाली बलिदान के बारे में देश और विशेषकर युवाओं को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शौर्य गाथाएं शिक्षा का अभिन्न अंग हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शहीदी धाम पर राष्ट्रपति से मिलना खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार सीता माता अभ्यारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़, बेणेश्वर के लिये सर्किट बना रही है। यहां के आदिवासी लोगों के लिये ''आदि गौरव सम्मान'' की शुरुआत की गयी है। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड के लिये विशेष रेल चलवाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों के भत्तों में बढ़ोतरी के बारे में भी जानकारी दी। शर्मा ने मानगढ़ विकास के लिये 5 करोड़ रुपये एवं पुलिस चौकी स्थापित करने की घोषणा भी की।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आदि गौरव सम्मान शुरु करके अच्छी पहल की है। अगर कोई जल-जंगल-जमीन बचा रहा है तो वे आदिवासी हैं और आदिवासी ही प्रकृति का संरक्षण करते हैं क्योंकि वे संस्कृति और परम्परा की जड़ों से जुड़े हैं।

समारोह में अनेक लोगों को तथा पंचायतों को ''आदि गौरव सम्मान'' से सम्मानित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के उपवर्गीकरण की समीक्षा याचिकाएं खारिज कीं

गत 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायलय ने एस.सी. तथा एस.टी. के आरक्षण में उपवर्गीकरण को सही ठहराया था

- **सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए कई याचिकाएं दायर हुई थीं। मुख्य न्यायाधीश सहित सात न्यायाधीशों की बैंच ने 1 अगस्त 2024 के फैसले की समीक्षा की मांग अस्वीकार कर दी।**

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण में उप-वर्गीकृत कर वंचित समूहों को तरजीह देने की अनुमति देने से संबंधित एक अगस्त 2024 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली सभा याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार के बाद पिछले दिनों अपना फैसला दिया। पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर कहा कि एक अगस्त के उसके फैसले में रिकॉर्ड को देखते हुए उसमें उसे कोई त्रुटि नहीं दिखती है।

पीठ ने कहा उच्चतम न्यायालय रूल्स 2013 के आदेश नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है।

शीर्ष अदालत ने मामले में खुली अदालत में सुनवाई के लिए एक आवेदन को भी खारिज कर दिया।

उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, समीक्षा याचिका पर दस्तावेजों के आदान-प्रदान के माध्यम से अधिवक्ता की उपस्थिति के बिना न्यायाधीशों के कक्ष में विचार किया जाता है। शीर्ष न्यायालय ने एक अगस्त, 2024 के अपने फैसले में एस.सी. और एस.सी. के उप-वर्गीकरण को संवैधानिक रूप से स्वीकार्य माना था। न्यायालय ने अपने फैसले में एस.सी./एस.टी. के बीच भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने का समर्थन किया था।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की मां ने 25 जुलाई, 2021 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह अपनी 16 साल की बेटी और बेटे के साथ किराए के मकान में रहती है। तीन साल पहले अभियुक्त उसके बेटी और बेटे का धर्म का भाई बनकर उनके साथ ही रहने लगा। इस दौरान अभियुक्त बेटे की कभी-कभार आर्थिक मदद भी कर देता था। इस दौरान अभियुक्त उसकी बेटी से फोन पर अश्लील बातें करता था, जिसकी जानकारी उसे नहीं हुई। वहीं, 27 जून को उसके बेटे को मारपीट के मामले में जेल हो गई थी। इस पर अभियुक्त मदद के नाम पर 7 जून को पीड़िता को अपने साथ ले गया।

अभियुक्त ने एक फ्लैट में ले जाकर पीड़िता को नशीला पानी पिलाया और बेहोशी की हालत में उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद भी अभियुक्त ने कई बार उससे गलत काम करने का प्रयास किया। ऐसे में अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि मामले में रिपोर्ट कई दिनों बाद दर्ज कराई गई है। इसके अलावा, उसने पीड़िता के जीजा को रुपए उधार दिए थे। जब उसने उधार लौटाने को कहा तो दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया और उसे इस मामले में फंसाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

भाजपा छोड़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विश्वास नहीं है। उन्होंने हरियाणा की जनता, खासतौर दलितों, पिछड़ों तथा समाज के वंचित वर्ग से अपील की कि वे शनिवार को विधानसभा चुनावों के लिये होने वाले मतदान में कांग्रेस को वोट दें ताकि हरियाणा फिर से एक नम्बर का राज्य बन सके।

यहाँ कांग्रेस मुख्यालय पर ए.आई.सी.सी. कोषाध्यक्ष अजय माकन के साथ, एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को सम्बोधित करते हुये अशोक तँवर ने कहा कि उन्होंने भाजपा इसलिये छोड़ी, क्योंकि वह लोगों को बाँटने के लिये जाति एवं धर्म की मदद लेती है, जबकि राहुल गांधी संविधान को बचाने तथा देश को संगठित करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

माकन ने कहा कि तँवर के विस्तृत अनुभव से कांग्रेस को हरियाणा में फिर से एक मजबूत पार्टी बनने में मदद मिलेगी।

मां-बेटी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हमलों से ग्रामीणों में, खासकर वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जोरदार गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले भी केवलों का खेड़ा गांव में ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी करते हुए उन्हें वहां से दौड़ाया था। कर्मचारियों ने स्कूल में बंद होकर अपनी जान बचाई। बाद में एस.डी.एम. नरेश सोनी, थानाधिकारी शैतानसिंह नाथावत और उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाया।

विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे

विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

- **विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा सिर्फ एस.सी.ओ. समिट के लिए हो रही है, इससे अधिक कुछ भी देखने की जरुरत नहीं है।**

नयी दिल्ली, 04 अक्टूबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 एवं 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान जाएंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज यहां नियमित ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले एस.सी.ओ. शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

एस.सी.ओ. शिखर-सम्मेलन के इतर मेजबान पाकिस्तान के साथ मंत्रिस्तरीय द्विपक्षीय बैठक होने और भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के दरवाजे खुलने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री की यात्रा सिर्फ एस.सी.ओ. शिखर सम्मेलन के लिए हो रही है। इससे अधिक कुछ देखने की जरूरत नहीं है।

हालांकि बैठक में शामिल होने वाले अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों के बारे में उचित समय पर जानकारी साझा की जाएगी।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) को फिर से जीवित करने की पैरोकारी किये जाने पर जायसवाल ने कहा कि हम क्षेत्रीय सहयोग को, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को गहरा महत्व देते हैं इसलिए हमने दक्षेस पर बिम्सटेक को प्रोत्साहन दिया है। हम क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह सभी जानते हैं। उस प्रारूप में यह विशेष सहयोग (दक्षेस) आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। एक विशेष देश के पास काम करने का एक विशेष तरीका है, जो दक्षेस को बाधित कर रहा है।

भारतीय भगोड़े इस्लामिक प्रचारक ज़ाकिर नाइक के पाकिस्तान में स्वागत सत्कार को लेकर एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा, हमने रिपोर्टें देखी हैं कि वह (जाकिर नाइक) पाकिस्तान में प्रवेश कर चुका है और वहां उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। यह हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि एक भारतीय भगोड़े का पाकिस्तान में उच्च स्तरीय स्वागत किया गया है। यह निराशाजनक और निंदनीय है लेकिन आश्चर्य की बात कतई नहीं है।

ऑपरेशन में आँख खराब होने पर अस्पताल पर 16.61 लाख का जुर्माना

- **जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि ऑपरेशन में लापरवाही से आँख में इन्फेक्शन हुआ और आँख की पुतली खराब हो गयी।**
- **आयोग ने डॉक्टर राजकुमार शर्मा और डॉ.आर.एम. सहाय मैमोरियल हॉस्पिटल पर यह जुर्माना लगाया।**

जयपुर, 4 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही से मरीज की आंख खराब होने को गंभीर कृत्य एवं सेवा दोष बताया है। इसके साथ ही, आयोग ने ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक राजकुमार शर्मा व डॉ. आर.एम. सहाय मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर 16.61 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने विपक्षी को निर्देश दिए हैं कि वह ऑपरेशन व लेंस के लिए परिवादी से वसूले 18 हजार रुपए उसे परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश शकुंतला देवी के परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि परिवादिया के ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही से उसकी आंख में इंफेक्शन हुआ और उसकी आंख की पुतली खराब हो गई, जिससे उसकी रोशनी हमेशा के लिए चली गई।

मामले के तथ्यों से भी यह साबित है कि विपक्षी डॉक्टर ने उसकी आंख का सही तरीके से ऑपरेशन नहीं किया।

परिवाद में कहा गया कि परिवादिया ने दांयी आंख में परेशानी होने पर विपक्षी डॉक्टर के घर पर 19 दिसंबर 2005 को दिखाया। इसके बाद 17 दिसंबर, 2006 को उसकी आंख में इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी आंख में कई दिनों तक दर्द रहा। वह लगातार डॉक्टर के संपर्क में रही और उसके अनुसार ही दवाइयां लेती रही। इस दौरान 24 सितंबर 2008 को उसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई, जिस पर 26 सितंबर 2009 को डॉक्टर राजकुमार ने उसकी आंख का ऑपरेशन कर दिया और इसके लिए लेंस व ऑपरेशन के 18 हजार रुपए परिवादिया से लिए। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद जब उसकी आंख की पट्टी खोली गई तो उसे दिखाई नहीं दिया और पुतली भी सफेद हो गई। परिजनों ने जब इस संबंध में डॉक्टर से पूछा तो उसने आंख में दवाई डालने के लिए कहा, लेकिन आंख में सूजन व इंफेक्शन हो गया।

क्षत्रप...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की चलने लगती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा ने तँवर को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। उन्होंने दलित नेता कुमारी सैलजा द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों को भी टिकट नहीं दिया था।

कांग्रेस के अन्दर अपने प्रतिद्वंदियों का इसी प्रकार का बहिष्कार राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह तथा कमलनाथ ने, छत्तीसगढ़ में भूपेन्द्र बघेल ने, उत्तराखण्ड में हरीश रावत ने, पंजाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने तथा हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह ने किया था।

यहाँ तक कि ये क्षत्रप राहुल गांधी के समर्थकों पर भी प्रहार करते हैं और राहुल बेबस देखते रह जाते हैं।

क्या मोहन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वे मोदी और भागवत, दोनों में से किसी के भी एजेंडा को क्रियान्वित न कर सकें।

मोदी, गडकरी तथा वसुंधरा राजे सिंधिया तक को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि सिंधिया बड़ी अड़ियल नेता मानी जाती हैं।

वे उस समय भी मोदी-शाह के सम्मुख नहीं झुकी थीं, जब वे दोनों राजे को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहते थे। सिंधिया ने धमकी दे दी थी कि वे पार्टी को तोड़ देंगी तथा अपने समर्थक विधायकों के बल पर सरकार बना लेंगी।

गतिरोध जारी है तथा यह स्थिति महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद तक चल सकती है। अगर भाजपा चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार जाती है, जैसी कि अटकलें लगाई जा रही हैं, तो आर.एस.एस. के सामने काफी कमज़ोर नरेन्द्र मोदी होंगे।

अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है और कटुता भी बढ़ सकती हैं।

वेतनमान कम करने के शिक्षा विभाग के आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द किया

- **शिक्षा विभाग में 2006 में अनुकंपा पर नियमित वेतनमान में नियुक्ति दी गयी थी। बाद में उसे फिक्स वेतन पर करने के आदेश निकाले थे।**

जयपुर, 4 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा पर नियमित वेतनमान पर दी गई नियुक्ति को बाद में फिक्स वेतन पर करने के शिक्षा विभाग के 10 मई, 2006 को जारी आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को स्वतंत्रता दी है कि वे याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका देते हुए तीन माह में नया आदेश जारी करें। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नया आदेश जारी करने तक वसूली की कार्रवाई प्रभावी नहीं रहेगी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश अनूप सिंह डागुर की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

याचिका में, अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को 27 फरवरी, 2006 को अनुकंपा के तहत नियमित वेतनमान पर शिक्षा विभाग में एल.डी.सी. पद पर नियुक्त किया गया था। जहां उसने कार्यग्रहण कर दो माह तक नियमित वेतनमान भी प्राप्त किया। वहीं, विभाग ने अचानक 10 मई, 2006 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को नियमित वेतनमान के स्थान पर दो साल तक परिवीक्षा पर रखने और इस दौरान फिक्स वेतन देना तय किया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को बीते महिनों में दिए नियमित वेतनमान की रिकवरी भी निकाल दी। याचिकाकर्ता से कहा गया कि उसकी अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के तहत हुई है।

इन नियमों में फिक्स वेतन देने का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, एक बार नियमित वेतनमान पर नियुक्ति देने के बाद उसे फिक्स वेतन में नहीं बदला जा सकता।

याचिका में यह भी बताया गया कि विभाग ने उसकी नियुक्ति के बाद एक आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर वेतनमान में बदलाव किया है। इस दौरान याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई मौका भी नहीं दिया गया। दूसरी ओर विभाग की ओर से कहा गया कि विभाग के नियमों के तहत कर्मचारी को नियुक्ति के शुरुआती दो साल परिवीक्षा के तौर पर फिक्स वेतन पर रखा जाता है।

हाईड्रोजन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से चलने वाले पाँच मेन्टिनेंस वाहन भी विकसित किये जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 10 करोड़ रु. है।

भारतीय रेलवे के अधिकारियों का अनुमान है कि एक हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण -व्यय 80 करोड़ रु. होगा, जबकि ग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिये 70 करोड़ रु. का निवेश अलग से करना होगा।

'ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस' नामक एक कम्पनी ने जींद में रीफ्यूलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्थापित कर दी है, जो प्रत्येक ट्रेन के लिये 1 मेगावाट पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन (पी.ई.एम.) इलेक्ट्रोलाइजर सप्लाई करेगी।

इस कम्पनी के एक अधिकारी ने कहा कि यह प्लांट, जिसमें 3000 किग्रा. हाइड्रोजन एक स्टोरेज यूनिट, एक कम्प्रेसर तथा दो हाइड्रोजन के लिए डिस्पेंसरर्स शामिल हैं, रोजाना 430 किग्रा. हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा।

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल विस्तृत नक्सली ऑपरेशन चला रहे हैं

- **राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारायणपुर दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों व नक्सलियों की मुठभेड़ की पुष्टि की तथा सुरक्षाबलों की सफलता पर बधाई दी।**

नारायणपुर, 04 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में चल रहे अब तक के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में शुक्रवार को सुरक्षा बल के जवानों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया। नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर अबूझमाड़ क्षेत्र में यह मुठभेड़ नेंदूर एवं थुलथुली गांव के जंगलों में हो रही थी। पुलिस तथा नक्सलियों के बीच आज दोपहर से ही मुठभेड़ जारी है, जिसमें करीब 28 नक्सलियों के शव बरामद किये गए हैं।

राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षाबल के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। साय ने कहा, जवानों को मिली यह बड़ी कामयाबी सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी। प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने इस मुठभेड़ में 30 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने दावा किया कि इस मुठभेड़ में शामिल सुरक्षा बलों के जवानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

मौके से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में एके 47, एसएलआर सहित कई अन्य हथियार भी बरामद किये हैं। यह मुठभेड़ नेंदूर और थुलथुली गांव के जंगलों में हो रही थी।

बताया जाता है कि गुरुवार को डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के थाना ओर्चा तथा बारसूर क्षेत्र के गांव गोवेल, नेंदूर एवं थुलथुली की ओर सर्च अभियान के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान आज अपराह्न लगभग 12:30 से 1:00 बजे के बीच पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान अभी भी जारी है।

इस साल बस्तर क्षेत्र में अलग-अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 171 नक्सलियों को मार गिराया गया है। बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा और नारायणपुर सहित 7 जिले शामिल हैं। उधर, 11 दिन में यह तीसरी मुठभेड़ है। 24 सितंबर को भी सुकमा जिले में मुठभेड़ हुई थी।

इस दौरान एनकाउंटर में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया था। हालांकि दोनों शव को उनके साथी अपने साथ ही ले गए।

मिर्जापुर में ट्रक-ट्रेक्टर ट्रॉली भिड़ंत में 10 मरे

उत्तर प्रदेश, 04 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गुरुवार देर रात एक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि यह दुर्घटना देर रात करीब एक बजे मिर्जापुर-वाराणसी सीमा पर कछवां और मिर्जामुराद के बीच जीटी रोड पर हुई। एस.पी. ने बताया, ''ट्रैक्टर-ट्रॉली में 13 मजदूर थे जो भदोही जिले में निर्माण कार्य करके लौट रहे थे, तभी उनके वाहन को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया।'' सूचना मिलते ही एसपी अभिनंदन और अन्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

एस.पी. ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर उन्हें शवगृह भेजा है और घायलों को तुरंत ट्रॉमा सेंटर (काशी हिंदू विश्वविद्यालय) वाराणसी भेजा गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इस संबंध में कछवां थाने में मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के लिये दो-दो लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है।

मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908